

ग्रा.वि.-14(पू)अर0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री शिवनंदन प्रसाद सिंह,

निबंधित

।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज, अररिया)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप रानीगंज प्रखंड (जिला-अररिया) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
31962.36073	₹ 43788434.200000003

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 31962.36073 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
प्रदीप कुमार,
सचिव

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, it is requested that the Government may also be intimated to this Ministry.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

The implementation of work under the NREGA should be done in cash. This is in accordance with the guidelines issued by the Government. The Government should ensure that the work is completed by the end of the financial year. The Government should also ensure that the work is done in accordance with the guidelines issued by the Government. The Government should also ensure that the work is done in accordance with the guidelines issued by the Government. The Government should also ensure that the work is done in accordance with the guidelines issued by the Government.

The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. The Government should ensure that the work is completed by the end of the financial year.

The Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

विश्वर त्रिपाठी,
प्रधान सचिव विकास विभाग

(Asstt. Secretary)
Joint Secretary

सचिव, विश्वर त्रिपाठी, अवर सचिव, विकास विभाग,
ई वि. वि. १००/०५

प्रतिनिधि, नवी उप विकास आयुक्तों को सूचना देकर
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वर त्रिपाठी
सरकार के उप सचिव।

New Delhi
Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified.*

30/12/05

Sir/Madam.

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

M. M. M.
22/12/05
4/11/05

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

58
11/06

Contd...2/-

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
क: ग्रामीण प्रकोष्ठ
राजदी हत्या

जिला का नाम:- अररिया

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री बाल्मीकि प्रसाद				12953317.12	1575725.9	127957445.3
2	श्री कल्या चौधरी						
3	श्री जी०ई० दास						
पंचायत समिति/ प्रखंड का नाम:-							
क्रम सं०	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री शिव शंकर मिश्रा (1973/2011)						
1	श्री जफर रकीब (1973/1999)	6290.41	4666	1624.41	2225441.7	324900	1900541.7
2	श्री महेफुज आलम (1973/1999)				3404258.2	0	3404258.2
2	श्री रहमतुल्ला (1306/1999)						
3	मो० परवेजउल्लाह (2262/1999)						
3	श्री अरुण कुमार	41747.82	10581.53	31166.29	42697817.3	111971	42585846.3
3	श्री सजय कुमार						
4	श्री शमीम अहमद (1905/1999)						
	श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी						
	श्री शिवानंदन प्रसाद	11067.29	9903.81	1163.48	1593967.6	108058	1485909.6
	श्री रमेश झा						
5	श्री विजय रंजन	15553.52	7704.56	7848.96	10753075.2	54440	10698635.2
6	मो० जफर रकीब (1821/1999)	21564.56	6989.42	14575.14	19967941.8	23855.3	19729388.8
7	मो० शमीम अहमद (1905/1999)						
	श्री अशोक कुमार तिवारी	7084.32	5760.39	1323.93	1813784.1	167277	1646507.1
	श्री सुरेन्द्र राय (1218/1999)						
	श्री शिवानंदन प्रसाद सिंह						
8	श्री शिवशंकर मिश्रा	52544.4	20469.36	32075.13	43942928.1	154493.9	43788434.2
	श्री सुरेन्द्र राय (2218/1999)						
	श्री राधा मोहन राम	6068.72	3781.16	2287.56	3133957.2	416033	2717924.2
9	सिकंदी						
	श्री अनिल कुमार (2352/1999)						
	Grand Total	161921.04	69856.23	94549.76	129533171.2	1575725.9	127957445.3